



UPSI120000542003

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ- सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3421

दाण्डिक वाद संख्या-618/2003

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन।

बनाम

01. रामचन्द्र यादव पुत्र बीरबल यादव,
02. भगौती प्रसाद पुत्र बीरबल यादव,
03. विनोद कुमार पुत्र रोहनलाल यादव,
04. सुशील कुमार पुत्र गोवर्धनलाल यादव, निवासीगण ग्राम व थाना सकरन, जिला सीतापुर।

.....अभियुक्तगण।

अपराध संख्या-129/2003

धारा-323, 324, 504, 506, भा०दं०सं०

थाना सकरन, जनपद- सीतापुर।

निर्णय

वादी मुकदमा रामफल, के द्वारा थाना सकरन, जनपद सीतापुर की पुलिस को दी गयी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना सकरन की पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण रामचन्द्र यादव, भगौती प्रसाद, विनोद कुमार व सुशील कुमार के विरुद्ध अपराध संख्या-129/2003, अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 506, भा०दं०सं०, के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन कथानक अनुसार वादी मुकदमा रामफल के द्वारा थाना सकरन जनपद सीतापुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करवाई गई कि प्रार्थी रामफल पुत्र चंदीदीन यादव निवासी ग्राम व थाना सकरन जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ। दिनांक 30/08/2003 को मेरे भतीजों अन्नू व गोवर्धन लाल को लड़कों से बातों बातों में विवाद हो गया था। उसी विवाद को लेकर आज समय करीब 8:00 बजे बच्चों बच्चों के वाद विवाद में दोनों पक्ष सुलह समझौते की बात कर रहे थे कि विपक्षीगण रामचंद्र पुत्र बीरबल, विनोद पुत्र रोहन, भगौती पुत्र बीरबल, सुशील पुत्र गोवर्धन निवासीगण उपरोक्त ने गंदी गंदी गालियां देते हुए लाठी डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरे चिल्लाने पर श्रीमती फूलमती पत्नी रामफल, पुत्र नागेश्वर, परशुराम, प्रमोद कुमार पुत्र राम शंकर व अन्य बहुत से लोगों के आ जाने पर विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। सूचना को आया हूँ। मेरी सूचना दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर पर पुलिस थाना सकरन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 129/2003, अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा०दं०सं० पंजीकृत कि गयी तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना का मानचित्र बनाया गया एवं घटना के गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण रामचन्द्र यादव, भगौती प्रसाद, विनोद कुमार व सुशील कुमार के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 506, भा०दं०सं० का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा सम्मन के माध्यम से तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा अपने जमानतनामों दाखिल किये। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्राप्त करायी गयीं।

दिनांक 18.06.2008 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 506, भा०दं०सं० विरचित किये गये। विरचित किये गये आरोप को

अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने विरिचित किये गये आरोप से इंकार किया और विचारण की याचना की।

अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्षियों के रूप में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है।

क्रम०सं०	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार
1.	श्रीमती फूलमती	मुख्य तथा प्रति परीक्षा

अभियोजन द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

क्रम०सं०	प्रलेख	प्रदर्श
1.	आरोप पत्र	—
2.	तहरीर	क ¹
3.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	—
4.	नक्शा नजरी	—
5.	मेडिकल एक्जामिनेशन रिपोर्ट रामफल	—
6.	मेडिकल एक्जामिनेशन रिपोर्ट फूलमती	—

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के विभिन्न प्रलेख की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया।

अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त दिनांक 10.06.2026 को अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को कोई मारपीट नहीं हुई, साक्षी पी०डब्लू० 1 श्रीमती फूलमती पी०के बयान के विषय में नहीं जानते, मुकदमा मारपीट का चला, बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व और कुछ नहीं कहना है, कहा।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं तर्कों को विस्तार से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

साक्ष्य विश्लेषण:— न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 506, भा०दं०सं० को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

साक्षी पी०डब्लू० 01 फूलमती ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि मेरे पति रामपाल की मृत्यु हो चुकी है। मुझे नहीं पता है कि मेरे पति ने किस वजह से मुकदमा लिखाया था। राम चंद्र, भगौती प्रसाद, विनोद कुमार, सुशील कुमार चारों मेरे भतीजे लगते हैं। इनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ था न ही इनके द्वारा मुझे मारा पीटा गया था न मेरे घर पुलिस आई थी। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह में साक्षी को धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने इंकार किया। यह कहना सही है कि बच्चों बच्चों में वाद विवाद हुआ था। समझा बुझाकर शांत करा दिया गया था परन्तु यह कहना गलत है कि बच्चों के विवाद को लेकर मेरे पति ने मुकदमा लिखवाया था जिसकी मुझे जानकारी है। यह भी कहना गलत है कि मैं भतीजों के दबाव में झूठी गवाही दे रही हूँ। न मुझे मारा पीटा था न गाली गुप्ता दिया था न मुझे जान से मारने की धमकी दिये थे।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू० 01 फूलमती ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि मुझे नहीं पता है कि मेरे पति ने किस वजह से मुकदमा लिखाया था। राम चंद्र, भगौती प्रसाद, विनोद कुमार, सुशील कुमार चारों मेरे भतीजे लगते हैं। इनसे

मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ था न ही इनके द्वारा मुझे मारा पीटा गया था न मेरे घर पुलिस आई थी। पत्रावली पर साक्ष्य का सूत्र का अवलोकन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त यह प्रतीत होता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी पी०डब्लू० 01 पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जाना सुरक्षित नहीं है।

चिकित्सा साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि चिकित्सा एक औपचारिक साक्ष्य होती है जो कारित हुई चोटों के सम्बंध में केवल अपना मत व्यक्त करता है। यह सही है कि ये चोटें अन्य कारणों से भी आ सकती हैं परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अभियुक्तगण के मारने पीटने से यह चोटें आयीं। इस तर्क के सम्बंध में न्यायालय अभियोजन के मत से सहमत नहीं है तथा **अभियोजन साक्ष्य में एवं चिकित्सा साक्ष्य में विरोधाभाष उत्पन्न होता है।** उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों में विरोधाभाष उत्पन्न होता है।

न्यायालय विशेषज्ञ रिपोर्ट मात्र से पदकार्य निवृत्त नहीं हो जाते (Court not functus officio because of expert opinion) न्यायालय पर विशेषज्ञ रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती है। विशेषज्ञ का कार्य एक राय तक ही सीमित है। मेडिकल साक्ष्य मात्र राय की साक्ष्य है और यह निर्णायक नहीं बन सकती है। **(मनीराम बनाम स्टेट आफ राजस्थान, ए०आई०आर० 1993 एस०सी० 2453)**

चिकित्सक द्वारा इस बावत केवल संभावना व्यक्त की गयी है। चूंकि चिकित्सक एक चश्मदीद साक्षी नहीं होता है केवल औपचारिक साक्षी होता है। इसलिए किसके द्वारा चोट कारित की गयी हैं इस बारे में कोई ब्यान नहीं दे सकता है केवल इतना बता सकता है कि ये चोटें किस प्रकार के हथियार से आ सकती हैं अथवा किस प्रकार से गिरने अथवा किसी चीज से टकराने अथवा किसी नुकीली चीज से टकराने से भी आ सकती हैं।

दौरान अंतिम बहस बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष ने प्रथम दृष्टया घटना को प्रमाणित नहीं किया है और अभियोजन अतिरिक्त किसी भी प्रकार के साक्षियों को न्यायालय में पेश करने में असमर्थ रहा है। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष अनुपस्थित है।

Ram Manohar and others Vs. State of U.P. – Criminal Appeal 2109 of 1980 September 27, 1999 (Allahabad High Court)—Criminal Trial—The prosecution story has been reconstructed and evidence has been attempted to be tailored— Prosecution evidence does not stand a close scrutiny— Therefore, accused are entitled to be benefit of doubt. Touching the different aspects of the case in the light of the judicious evaluation of the evidence on record, we are of the opinion that the prosecution story has been reconstructed and the evidence has been attempted to be tailored accordingly. But several unpatchable holes are visible and the evidence of the prosecution does not stand a close scrutiny. The ocular version also as discussed hereinabove. For the reasons contained in the discussion made hereinabove, we finally reach the conclusion that the prosecution case against the accused are entitled to the benefit of doubt.

Muneshwar Singh Vs, State OF U.P.— Reference No. 9 of 1999 and Cr. A. No. 1798 of 1999 May 10, 2000 (Allahabad High Court) Criminal Law— Jurisprudence— Settled law— Prosecution has to prove the guilt of accused beyond all reasonable doubt— Any number of culprits may go scot free but a single innocent person should not be punished. The well settled law of criminal jurisprudence is that it is for the prosecution to prove the guilt of the accused beyond all reasonable doubt. The criminal jurisprudence follows the eternal principle that any number of culprits may go scot— free but not a single innocent person should be punished. The present case against the accused seems to be largely built on suspicion

only. There fore, On over all consideration of the Evidence and Circumstances accused entiled to benefit of doubt.

Sitaram Seth and others Vs. State of U.P. [2014 (85) ACC 182] – Criminal Appeal 2758 of 1985, March 11, 2014 (Allahabad High Court)
Burden of prosecution– Never shifts– No good reason advanced by the deceased in support of his plea of false implication– Cannot be a ground to hold him guilty– Burden always on the prosecution to establish it's case by adducing natural and reliable evidence. For the aforesaid reasons we are of the view that the prosecution has been unable to produce cogent and reliable evidence for establishing the complicity of the crime.

अतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा गहनता से किये गये सम्यक परिशीलन से अभियोजन कथानक पर सन्देह से परे विश्वास नहीं किया जा सकता है। साक्षी द्वारा घटना को प्रमाणित नहीं किया गया है और उक्त साक्ष्य को भी विवेचक तथा चिकित्सक के प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है, जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी हैं। दण्डिक विधि का प्रतिस्थापित सिद्धान्त है कि साक्ष्य का भार पूर्णतः अभियोजन पर होता है। अभियोजन को सन्देह से परे यह साबित करना होता है कि अभियुक्त द्वारा ही कथित अपराध कारित किया गया है और यदि अभियोजन द्वारा अपने कथानक को सन्देह से परे साबित नहीं किया जाता है तो अभियोजन की निर्बलता व कमियों का लाभ सदैव अभियुक्त को मिलता है। अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारण न्यायालय द्वारा तब तक की जाती है जब तक अभियोजन द्वारा अभियुक्त को दोषी साबित नहीं किया जाता है।

अतः प्रस्तुत मुकदमें के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के अभिमत में अभियोजन पक्ष अपना केश सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा अनुपस्थित है, जिस कारण अभियुक्तगण **रामचन्द्र यादव, भगौती प्रसाद, विनोद कुमार व सुशील कुमार** पर लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **रामचन्द्र यादव, भगौती प्रसाद, विनोद कुमार व सुशील कुमार** पर लगाये गये आरोप अपराध संख्या 129/2003, अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना सकरन, जनपद सीतापुर से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं उनके जमानतनामों निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगणों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

दिनांक 21.07.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतापुर।

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज दिनांक 21.07.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 21.07.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/-